GOVERNMENT BILLS

The National Institute of Fashion Technology Bill, 2005

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shankersinh Vaghela to move the Bill.

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): Sir, I move:

> "That the Bill to establish and incorporate the National Institute of Fashion Technology for the promotion and development of education and research in fashion technology and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्री अजय मारू (झारखंड): धन्यवाद, उपसभापति महोदय। आज के समय में फैशन टेक्नोलॉजी का महत्व काफी बढ़ गया है। पिछले महीनों जब फैशन शो के माध्यम से मुम्बई हो या दिल्ली, दोनों जगहों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटीं, जिससे फैशन उद्योग काफी चर्चा में आ गया। महोदय, यह विधेयक राज्य सभा में 23 दिसम्बर, 2005 को लाया गया था, लेकिन उसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि वस्त्रों, जीवन शैली के उत्पादों और अन्य फैशन-सम्बन्धी भारतीय उत्पादों की उपयोगिता अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है और इस क्षेत्र में काम करने की बहुत गुंजाइश है। जैसा कि इस बिल, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2005 में कहा गया है कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1986 में की गई थी और उसके पश्चात् विशेषकर पिछले एक दशक में, इस फैशन उद्योग के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति आई। आज फैशन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग का स्थान ले चुका है। आज हमारे देश से अकेले टेक्सटाइल का जो निर्यात होता है, वह तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है। पहले हम फैशन प्रौद्योगिकी को केवल कपड़े या designer wear के रूप में देखते थे, पर आज फैशन में कपड़ों के अलावा हमारी जीवन शैली में प्रतिदिन उपयोग में आने वाले अन्य उत्पादों में भी इस प्रौद्योगिकी ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। जिसमें चमड़े से संबंधित उत्पाद, गहने या हैंडीक्राफ्ट या उत्पाद में इंफोरमेशन टेक्नोलोजी आदि का प्रमुख स्थान हो गया है।

महोदय, आज जिन चीजों को लेकर यह बिल सदन में लाया गया है, उनमें किसी को विरोध नहीं हो सकता, लेकिन मैंने पहले भी कुछ विधेयकों को देखा है और इस विधेयक में भी एक बात नजर आ रही है और वह है स्वायतता प्रदान करने की, वहीं दूसरी ओर अपना नियंत्रण

बनाए रखने के लोभ से भी सरकार अपने को नहीं बचा पाई है। विधेयक में शासक बोर्ड के गठन से लेकर हर जगह सरकार का नियंत्रण व हस्तक्षेप बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण पदों पर या तो सरकारी अधिकारी रहेंगे या केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो मनोनीत व्यक्ति हैं, वही रहेंगे। कहीं कहीं पर विशेषज्ञों की बात जरूर कही गई है, पर प्रमुखता सिर्फ सरकारी अधिकारियों को ही दी गई है। हमें इससे बचना चाहिए तथा संभव हो तो संस्था को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी जानी चाहिए। इस बिल के संबंध में श्रम मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने जब अपनी बारहवीं रिपोर्ट पेश की थी, तो उन्होंने इस प्रबंधन समिति में लोक सभा के दो और राज्य सभा के एक सदस्य की भी अनुशंसा की थी कि वे भी इस प्रबंधन समिति में रहें, लेकिन इस बिल में स्टैंडिंग कमेटी की उस अनुशंसा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न ही इसका कहीं कोई जिक्र किया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो अनुशंसा स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी कि लोक सभा के दो और राज्य सभा का एक सदस्य इसकी गवर्निंग बोडी में रहें, उस पर भी विचार किया जाए।

महोदय, आज पूरे देश में कई निजी संस्थान भी हैं, जो फैशन प्रौद्योगिकी के स्कूल या ऐसे संस्थान चला रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्स्टाइल ने एक उत्साहवर्द्धक लक्ष्य जो इसके विकास का रखा है, वह प्रतिवर्ष 8 से 9 प्रतिशत का है। एक अनुमान है कि वर्ष 2010 तक भारत में इसका निर्यात 10 बिलियन यूएस डॉलर तक का हो जाएगा और अगर हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो वर्ष 2010 के बाद हम इस उद्योग के माध्यम से एक करोड़ बीस लाख लोगों को नई नौकरियां दे पाएंगे। इससे भी इस बिल का महत्व और बढ़ जाता है। आज फैशन प्रौद्योगिकी हमारे युवा-वर्ग में कैरियर का एक महत्वपूर्ण विकल्प हो गया है और इन सभी संस्थानों में जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनमें 75 प्रतिशत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो नोन-मेट्रो सिटीज से आते हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों, दोनों का अनुपात बराबर का होता है। निफ्ट जैसी संस्थान में पहले एक कमी थी और वह यह थी कि यह जो चार साल का कोर्स और दो साल का कोर्स चला रहे थे, उसके लिए स्टूडेंट्स को केवल डिप्लोमा देते थे, डिग्री नहीं देते थे। अब कैबिनेट में इस पर विस्तार से विचार किया गया और कई मंत्रालयों के विचार-विमर्श के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि यहां पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ डिप्लोमा ही न दिया जाए, डिग्री भी दी जाए। इस डिग्री के अभाव में विश्व स्तर में हमारे बच्चों को कम्पीट करने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और विदेशों में आगे पढ़ाई करनी पड़ रही थी जो डिप्लोमा से पूरी नहीं मानी जाती थी, अब डिग्री कोर्स के हो जाने के बाद यह दिक्कतें खत्म होंगी और इससे हमारे बच्चों को काफी फायदा होगा।

महोदय, विधेयक के ''वित्तीय ज्ञापन'' में बताया गया है कि वर्ष 2004-05 में संस्थान का राजस्व-आय राजस्व-व्यय के मुकाबले में अधिक है। यह भी बताया गया है कि विधेयक में

कोई व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा और भारत की संचित निधि पर कोई वित्तीय भार इसका नहीं पड़ेगा। सरकार ने जो अनुदान निफ्ट को पूर्व में दिया है, इसमें हर वर्ष कुछ न कुछ वृद्धि दी गई है, जहां वर्ष 1996-97 में प्लान और नोन-प्लान में 6 करोड़ 41 लाख रुपए का अनुदान था, वहीं यह बढ़ते-बढ़ते 2000-01 में 27 करोड़ रुपए तक का हो गया। इसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में 'निफ्ट' की जो सात शाखांए हैं, वे अपने भवनों में चल रही हैं, किसी भी रेंटिड भवन में ये शाखाएं नहीं चल रही हैं। इनकी शाखाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। पूर्व में NDA के शासनकाल में भी इनकी शाखाएं बढ़ी थीं, जिसका पूरा श्रेय उस समय के तत्कालीन मंत्री श्री काशीराम राणा जी और श्री शाहनवाज हुसैन को जाता है और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

महोदय, अभी पूरे देश में 'निफ्ट' के सात संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें से पूर्वी भारत में मात्र एक कोलकाता में है। विधेयक में व्यवस्था है कि शासक बोर्ड भारत में किसी स्थान पर या भारत से बाहर संस्थान के नए सेंटर स्थापित करने पर विचार करेगी। मेरा सुझाव है मंत्री महोदय से कि प्रत्येक प्रदेश में इसकी एक शाखा खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए और मेरे प्रदेश झारखंड में भी इसकी एक शाखा जल्द से जल्द खोली जाए। पाणी जी कह रहे हैं कि उड़ीसा में भी इसकी एक शाखा होनी चाहिए, मैंने सुझाव दिया है कि प्रत्येक प्रदेश में इसकी एक-एक शाखा खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, फैशन के मामले में जागरूकता अब सिर्फ बड़े शहरों तक की सीमित नहीं है, बल्कि मध्यम एवम् लघु नगरों में भी इस मामले में काफी दिलचस्पी पैदा हुई है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि संस्थान के केन्द्र भले ही बड़े शहरों में हों लेकिन इनकी गतिविधियां बड़े शहरों तक ही सीमित न रहें। संस्थान में शिक्षा की फीस और अन्य शुल्कों का ढांचा भी ऐसा होना चाहिए कि मध्यम आय के छात्र-छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सके।

विधेयक में फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व साहित्य और सामग्री एकत्र करने की बात कही गई है। इसका कोई विरोध नहीं है, मगर संस्थान के जो पाठयक्रम बने हैं या जो सामग्री तैयार हो, उसमें भारतीय संस्कृति और परम्पराओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। आज सम्पूर्ण विश्व में भारतीय वस्त्रों, पहनावों और सौंदर्य की अलग पहचान बनी हुई है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि विधेयक की धारा 6 में, जिसमें कहा गया है कि संस्थान के निम्नलिखित कृत्य होंगे, इस बात का उल्लेख होना चाहिए - 'ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहित करना जो भारतीय परम्परा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में सहायक हों।'

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक के पारित किए जाने का समर्थन करता हूं।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I rise to support the National Institute of Fashion Technology Bill, 2005. Sir, the world is passing through a big economic, I should say, blast. The development is taking place in every aspect, whether it is manufacturing sector or the service sector or the heavy industries sector or the science and technology sector or the agriculture sector. Obviously, the fashion technology cannot be left behind. It was in 1986 that the then Congress Government, with a vision of Shri Rajiv Gandhi, started this Institute, which is known as NIFT. I personally know a number of students who have studied in these institutes and who have become fashion czars, as we call it. Not only in this country, but these designers are being accepted in the world also. Like the Indian paintings, which are coming in a big way, the designers are going ahead in the world market. In this situation, the present Government wants to give more autonomy. I am with it. But, on the one hand, we give more autonomy to this Institute, and, on the other hand, we try to throttle the activities of this Institute by bureaucratic control. That has to be looked into. What is our serious intention? Do we want this Institute to develop at world level? Do we want this Institute, which is there at seven centres? As Marooji has said, I will also request the hon. Minister not only this Institute, we should have a centre in every State of the country. We should develop more and more private fashion institutes. When we are talking about globalisation, its impact should be on this also. If we control it by bureaucracy, it will not develop the way we want it to develop. Talent is available in the country. Sir, you have to use the best talent available in the country. That should be used for this Institute. Our students, who come out from the IIMs, and the IITs, are the world-class students. Similarly, this Institute also has to become a world-class institute. It can become a world-class institute only if we use the best talent.

Sir, obviously, when these students come out of it, they will add value to the products. Textile is one of the most important products, which is being exported. I think 29 per cent exports of the country are textiles. More and more other products, which are related to the fashion technology, are going outside the country. Because, for the last few years, we have had Miss Worlds and Miss Universe. All of us know that.

A number of beauties from our country have shown the world that India is not lagging behind in any kind of activities. When we come to fashion also, we cannot lag behind.

Indian fashion does not necessarily mean, as we call, less and less clothes or less and less coverage. The saying goes that sometimes you hide less but reveal more. So, it is not the question of fashion by revealing more; fashion can be displayed by hiding more. If we see fashion in our villages, that is equally good fashion. Sir, I know that European and American people nowadays want Indian *Maharajas* kind of dresses for their weddings. Why? Because that is becoming the fashion. That can be more acceptable. So, revealing more is not going to be the fashion.

Marooji has mentioned about fashion shows. Obviously, I am not against fashion shows, because shows are necessary for propagating what kind of fashions a country develop. If organisers with ulterior motives want to show something which should not be shown—जिसे हिन्दी में अश्लील बोलते हैं, इस तरह का काम हमारे कल्चर में एक्सैप्टेबल नहीं है—and if it is proved that any organiser is doing it, then strongest action against him should be taken under different laws available in the country. If the fashion is done in accordance with the culture of our country, we will welcome it. But it should be decently done.

Fashion is now not only confined to women. Nowadays men are equally interested in fashion. I would like to name anybody, but a number of our people, even may be some MPs, are interested in fashion. *Kurta payjama* is also a fashion.

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिम बंगाल): आप डा॰ सुब्बारामी जी की तरफ भी देख सकते हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया: जी हां, पहले मैंने देखा नहीं था, अब देख लिया। Our great friend, he is fashionable man. He is the leader of the fashion in our House. This is also the fashion, Sir. These things can be developed. It should be developed. I have no objection. When we come to the business side, Sir, I would like to draw the attention of the House and the Minister, through you, Sir, that the kind of volume of business which is developing in fashion and the kind of value addition is coming, the same jacket which my esteemed friend, Mr. Reddy, is wearing, I can tell you this jacket is available for, say, Rs. 500. But when Mr. Reddy wears it, it becomes worth Rs. 50,000. This is through fashion. So, the fashion value addition is quite a lot. That is what the country needs when we export. When we export anything with value addition, the total cost is much lesser and that will be a great plus point for the country's business. Sir, it is not the question

of ten billion dollars. It can be twenty billion dollars or it can be 40 billion dollars even now, of the whole world's total business available, even in the textile, India is handling hardly one per cent of the world's textile business. The scope is unlimited. It's the question of taking advantage of it. And at this time, if we keep our mind closed that we will not do this or that we will keep the bureaucratic control on every step of our activity, then, I am sorry, we will only be taking and giving lip-service to this technology. We will only be giving lip-service to the development of the country on this side; otherwise, the scope is unlimited and we should look into it from that aspect. I will request the hon. Minister to look into it.

Sir, there is another point which is very important, and Madam Karat will bear with me, we want women to be more active; we want more and more girls getting into it rather than household chores. They should become more productive and they can be more productive in fashion business. As we all know, in this Institute, the ratio is 50:50. In no other institute, you will find that girls are 50:50. Boys are many more. So, that is also one of the reasons if we develop this Institute more, more and more girls will come into this kind of activities. Girls understand fashion more than the boys do. This will be a great addition and help to the women and girls of our country who are coming out of the colleges and they will go into this line which is their line and they can do better business also.

Sir, this amendment was required, which was being tried since December 2005. But, unfortunately, it has been delayed for sometime because it went to the Standing Committee and the report has come. Basically, fashion does not mean only the cotton or silk or only the textiles. Fashion means everything—either it is jewellery fashion or it is made out of leather and even crafts are fashion. And when we think of fashion, even interior decoration is a fashion. It is by fashion that a number of things are put at home. These are all part of fashion. So, that is why, probably the hon. Minister and the Government wanted this amendment that all this should be included and I compliment him for this.

One issue was raised by our hon. Member just now regarding inclusion of three Members of Parliament in this. Well, I will be glad that one of our Members will be in this Governing Board. But I don't know what kind of service they will give to this Board because most of the MPs are not fashion-oriented. Mr. Reddy has become a Minister. So, he can't go there. Either he agrees to get out of the Ministry and goes as a Member

there. I have no objection. Then, he will give value to this Board. If I object to the bureaucratization of this membership, I also object to the politicisation of this. I do not suggest that there should be any bureaucratic control. At the same time, I suggest that there should be no political control. Members of Parliament have many more things to do. I personally think that they do not have to be involved in this kind of activity directly.

Lastly, I would like to say that the NIFT has decided to award degrees instead of diplomas. That is a very good idea. I would like to mention one more thing. I don't think that the Indian Maharaj, who is known as the chef in English, can go out of the country for service because they do not have the certificate. The Indian cooks are also very, very important people. It is a big technology. But, unfortunately, since no certificate is being given to them, they are not allowed to go to the US or the European countries for service because they have no certificate. Similarly, if degrees are given, it will be recognised, and they can work at the world level. Thank you very much.

SHRI SK. KHABIR UDDIN AHMED (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise not only to support the Bill, but also to welcome such a laudable Bill. Now, the Institute of Fashion Technology will not merely award diplomas, but the scope of the Institute has been broadened, firstly, to improve quality and excellence in education; secondly, to award degrees, and thirdly, to import still higher education in fashion technology, including research work. This will help the artisans to develop the level of their skills, and they would be able to compete in this field at the international level. Even then, I would like to make some points to enrich the Bill and to make it attractive for the grass-root level artisans.

In clause 3, sub-clause (3), there is a provision for constitution of the board. In sub-clause (f) of this clause, it is stated that there should be five persons from States in which the campus of the institute is located. But, it is not said whether this number of five persons should be increased in case the number of States having campus is increased.

In clause 6, details have been given in respect of the functions of the institute. I invite the attention of the hon. Minister to item no. XVI of this clause. Here, it speaks of technical assistance to artisans, craftsmen, manufacturers and designers etc. In this connection, I would like to emphasise the cases of the vast section of people working in the garments industry, in knitting profession, in embroidery which are wide spread in

1.00 P.M.

cities, towns and villages, and where a large section of the talented young people are devoting their intellect and toil.

A provision is necessary to provide technological knowledge to the grass-root level artisans by way of short-term courses. Besides, how to help the handloom and khadi workers. We all know that there is a general crisis in the khadi industry. Suicides have taken place amongst the handloom workers. How could we intervene in that particular area? What provision is this Bill making for these large sections of rural artisans? We are having innumerous talented persons working in the self-help groups, spread over the whole of the country, particularly among the minorities, the SCs/STs, the OBCs and other socially and economically depressed sections of the society. This Bill does not stand for giving priorities to these sections of young boys and girls. Should we stick to the elite and affluent sections alone? The Bill should have a provision to extend to the base level workers who are devoting their toils and intellects day and night to earn a bare livelihood. If necessary, I propose to being amendments to extend its approach to the grass-root level of technicians in time to come.

Sir, in section 15, sub-section (5), the Central Government is assuming powers to remove the Director-General before the tenure of three years. It will not be wise to vest such powers of arbitration on the Central Government. I hope that democratic norms would be devised in this respect while preparing rules.

Sir, India is having a long and praiseworthy tradition of culture and style of its own. But nowadays, a tendency is found, to grow more and more, to expose the western culture and style. Growing up our own beautiful style, our teachers, professors, the courses of studies and technical experts should take a proper view in that respect.

Let fashion run with the call of ages. The newer generations must have attachment to the taste of the growing civilisation. But the inner significance of the Indian civilisation must be restored and be enlarged to attract the whole world to our growing fashions. Thank you, Sir.

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद महोदय, आज देश नहीं, बल्कि दुनिया में फैशन का जमाना आ गया है। इसके लिए आज फैशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की जरूरत है इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इससे फैशन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शिक्षा और अनुसंधान में क्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इसकी उत्कर्ष, विकास और संवर्धन में भी जरूरत

है। फैशन प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में जो डिग्रियां प्रदान करेगी, वह डिग्रियां देने की भी जरूरत है। फैशन टेक्नोलॉजी से शैक्षिक क्षेत्र को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार की वृद्धि होगी। इसके साथ-साथ निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हमारा एक सुझाव है कि कहीं फैशन के नाम पर जो आज लोग वस्त्रहीन होते जा रहे हैं या अर्ध नग्न होने जा रहे हैं या नग्न प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का जो नग्नता का प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस पर रोक लगाई जाएगी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Sir, the Government has brought this Bill before the House to give statutory status to the NIFT. The NIFT was established two decades ago, and the Government has, now, though it fit to make this Institute at par with other professional institutions with international benchmarking. The Bill has been examined by the SC on Labour, and that gave two substantive amendments. The first one is with regard to the definition of 'fashion', and the second one is to give representation to the Members of Parliament on the Board of Governors of the Institute. It is good that the Government, I understand, has accepted those recommendations.

Sir, NIFT has been emerging as one of the pioneering institutes in the country in the field of fashion designing with nearly 1,500 intakes every year. It is good that NIFT is fully funded by the Government. Now, with the proposed statutory framework, I hope that NIFT would transform fashion technology into a wealth-generating business by getting more assistance from the Government. I would suggest that there is a need to embed fashion technology into a textile industry which is very important for our economy.

The next point is, many people is semi-urban and even in urban areas are not aware that there is an institute in the country, which deals with fashion technology, fashion designing etc. Even it they know, they are only aware that it deals only in designing garments. Very few people know that NIFT provides courses even in leather garment designing, fashion communication, accessory designing etc. So, there is a need for bringing more awareness about fashion designing to make India a fashion capital of the world. If you look at the textile designing, the global supply and retail chain are the key characteristics of this industry. India has a tremendous opportunity in textiles in the area of design and supply chain logistics. Design costs in India are one-tenth of that in the U.S. and there

is a change in the sourcing pattern of buyers and most of them sourcing from centres close to the point of sale. So, there is big scope for India to become a design outsourcing hub and we should not miss this opportunity. India is doing somewhat better since January, 2005 when quotas on textile imports were lifted. The world trade in this segment has since then undergone a number of changes and presenting buyers with several options in sourcing. Of course, in just one year, Indian textile and apparel exports increased by 19 per cent to 16 billion dolars. This should be consolidated and doubled in the next 3-4 years.

The other point is that, in India, we are regularly having Fashion Shows where models display different designs. But in the recent wardrobe malfunction at Mumbai Fashion Week a halter of a designer's creation slipped off and in another incident another model's skirt was torn open. This is not for the first time that such things have happened. Earlier also such incidents have happened. But the Government of India is not taking any measures to prevent recurrence of such incidents. So, I urge upon the Government to issue some guidelines and make them to follow strictly.

Sir, you are upgrading this Institute to the status of an institute of excellence like IIT, IIM, etc. Now, the Government is seriously considering giving reservation to the OBCs in IITs and IIMs. If this materialises, would the Government also consider extending the same to the NIFT? If it would not, I wish to know the reasons behind that.

Finally, on the Board of Governors, you have only one representative from the Council of States. So, I suggest that instead of having one Member from the Rajya Sabha, you appoint two Members on the Board of Governors, with one lady Member as a Member on the Board. Thank you.

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, I would like to put to the Minister only two questions. As I know, in reality, fashion depends on our culture, not only in respect of our nation but also in respect of any nation. In this fast-changing world, cultural exchange is going on throughout the world. So, fashion is also changing. My specific question is: What type of action is the Government of India, particularly this Department, taking to meet the changes which are taking place throughout the world and in our country also? This is number one.

Number two is that some artisans who are working at the village

level and at the semi-town level, particularly in the textile fashion desgining, are very poor. They are good artisans of our country and they are residing in these particular areas. what type of training is the Government giving to them to uplift their ability and to face the changing situation? Why I am asking this question is that in the Financial Memorandum of the Bill the Government has stated that there is no need for providing funds from the Government exchequer and, therefore, the Bill does not involve any expenditure and there will be no financial burden on the Consolidated Fund of India. What type of action will the Government take to improve the condition or position, particularly, of these poor artisans? These are the two particular questions. Thank you.

श्री शंकर सिंह वाघेला: डिप्टी चेयरमैन सर, मैं सब मैम्बरों का आभारी हूं कि इन्होंने बहुत valuable, fashionable suggestions फैशन टैक्नालॉजी के बारे में दिए हैं और मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री पूरी कोशिश करेगी और जैसे भी हो, इसमें आप सबका सहयोग लेकर यह इंस्टीट्यूट खरा उतरेगा। सर, मैं जब टैक्सटाइल मिनिस्टर नहीं था, तो एन॰आई॰एफ॰टी॰ हमारे पास आएगा, इसकी कभी कल्पना भी नहीं थी। तक कुछ बच्चों ने हमें एप्रोच किया था कि हमको डिप्लोमा मिलता है, डिग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। तब पता नहीं था क्या करना पड़ेगा। जब मैं मंत्री बना और डायरेक्टर जनरल निफट और बोर्ड गवर्नर्स के साथ चर्चा हुई तो इन्होंने कहा कि इसके लिए तो बिल लाना पड़ेगा, कैबिनेट में जाना पड़ेगा। जैसा माननीय बागड़ोदिया जी ने बताया है कि हम कैबिनेट में गए और स्टेंडिंग कमेटी में एक बिल गया। स्टेंडिंग कमेटी ने खुद निफ्ट की विजिट की और जो सजेशन्स दिए, उनको ठीक करने के लिए कि डिप्लोमा नहीं डिग्री मिले, ताकि यहां से बाहर जाने के लिए भी सुविधा हो। हमारे बच्चे कहीं भी जाकर बता सकें कि हम डिग्री होल्डर हैं, इस हिसाब से इस बिल को लाना पड़ा है। माननीय सदस्य श्री मारू जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मेरी कल भी इस बारे में मेरी चर्चा हुई थी कि जो स्टेट निफ्ट सैंटर चाहते हैं, वे हमें प्रोपोजल भेजें। इसके लिए इनको बिल्डिंग की तथा व्यवस्था तथा खर्चे इत्यादि की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। अगर हमारी टर्म्स कंडिशन्स में ठीक रहेगा तो रांची, पटना या कहीं पर भी हो, अभी इसके 60 सैन्टर्स हैं। आने वाले दिनों में हम इसके लिए और कोशिश करेंगे। हमारी केरल सरकार से बात हुई थी। पंजाब से भी प्रोपोजल है। हमारी हरियाणा सरकार से भी बात हुई है, आसाम सरकार से भी बात हुई है, लेकिन इसके लिए एक कंक्रीट प्रोपोजल आना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वे अपनी राज्य सरकार के माध्यम से प्रोपोजल लाएं और जो भी खर्चा वे बेयर करेंगे, करें और इसके लिए हमारे पास स्टाफ होगा, यदि नहीं होगा तो हम नया स्टाफ भर्ती करेंगे, लेकिन निफट सैन्टर्स के लाभ हम जरूर बढ़ाएंगे। अभी यहां माननीय सदस्य श्री मारू जी ने कहा है और मैडम दुर्गा जी ने कहा है कि दिल्ली और मुम्बई में

फैशन डिजाइन के प्राइवेट शो होते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोई शरीर प्रदर्शन का मामला नहीं है। यह ठीक है कि कपड़े फैशन में आने के बाद आयोजक मॉडल्स को कपड़े पहनाकर, कभी-कभी बिलो स्टैन्डर्ड भी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वह सब ठीक नहीं होता है। इसलिए एक प्रोपोजल भी आई थी इनके लिए अन्डर गारमेंट्स को कम्पलसरी बनाया जाए, लेकिन जो प्राइवेट फैशन शो करेंगे, वे हमारे प्रव्यू में तो हैं नहीं, फिर भी कोई कम्पलशन होना चाहिए कि मॉडल्स को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। ये जो हादसे होते हैं, कभी ये जान-बूझकर किए जाते हैं या कभी अपने आप भी हो जाते हैं। यदि जानबूझकर भी हुआ होता है तो यह अच्छा नहीं होता है। इसलिए फैशन के नाम पर शरीर प्रदर्शन के मौके नहीं होने चाहिए। जब भी कभी हम किसी शो में जाते हैं तो पहले पूछ लेते हैं कि क्या प्रदर्शन होगा और यदि हम वहां पर जाएं तो क्या ठीक रहेगा या फिर उसका बिलो स्टैंडर्ड होगा तो वह ठीक नहीं रहेगा। हम पहले पूछ लेते हैं कि आप प्रदर्शन में क्या करने वाले हैं। कल ही अशोक होटल में सिल्क का एक फैशन शो था। वह बहुत ही अच्छा शो था। हमें यह लगना चाहिए कि एक डिगनिटी से यह फैशन हो रहा है। हम अपनी मिनिस्ट्री की ओर से फैशन शो करने वालों को यह जरूर लिखेंगे कि आगे इस प्रकार का कोई हादसा न होने पाए। इसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी स्टैप्स लेने चाहिएं, वे आप जरूर लीजिए। हमारे साथी माननीय बागड़ोदिया साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं समझता हूं कि जो ब्यूरोक्रेट कंट्रोल की बात है,

His Excellency, the President of India.

राष्ट्रपति जी इसके विजिटर रहेंगे। इस बिल में जो सुझाव हैं कि जो इसमें सदस्य होंगे, उनमें एक राज्य सभा सदस्य और दो लोक सभा सदस्य होंगे। मैं सभी पार्टियों से प्रार्थना करूंगा कि हो सके तो वे अपनी ओर से इसमें महिला एम०पी० को भेजें और उनमें भी वे महिला एम०पीज, जिनका थोड़ा बहुत फैशन की दुनिया से लगाव हो। अगर बहुत रिजिड मैंटेलेटी होगी तो मैं नहीं समझता कि इस बिल को कोई फायदा होगा। इसलिए जो मैम्बर्स इस कोटे में आते हैं कि ये मैम्बर्स निफट में जाएंगे, यदि हो सके तो उनमें लेडी एम०पीज को प्रियॉरिटीज दें और वह भी उनको जो कि फैशन एप्रोच वाली हों। इतना ही नहीं इसमें AICT के माध्यम से न्यूनतम स्टैन्डर्ड्स तय किए गए हैं, उनके हिसाब से चलेगा। वैल्यु एडिशन डायवर्सिफिकेशन बहुत हो रहा है। गारमेंट्स की इतनी डिमांड है कि अभी कोटा खत्म हो गया है। हमारा अमेरिका में अभी 26 परसेंट एक्सपोर्ट हुआ है, UAE में 18 परसेंट हुआ है, वहां पर इसकी और भी डिमांड है। अभी भी स्टूडेंट्स इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज तक तकरीबन पांच हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर गए हैं। इस क्षेत्र में एक भी स्टूडेंट अन-एम्पलायड नहीं है। इसकी इतनी डिमांड है कि इसमें 100 परसेंट जॉब की सिक्योरिटी है। माननीय सदस्य श्री बागड़ोदिया जी कह रहे थे कि जब मैं इसमें जाता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि आपका क्या नाम है और आप कहां से आए हो, तो उनमें कई

लड़कियां मारवाड़ी होती हैं, जो कि बहुत रिजर्वेशन वाली होती हैं, वे इतनी टाइट परम्परा में से आती हैं, मैं उन बच्चियों से कहता हूं कि तुम्हारे पैरेंट्स ने निफट में क्यों भेजा? वे कहती हैं कि हमारे पैरेंट्स ने कहा कि ठीक है, जहां भी जाना हो, तुम जाने के लिए फ्री हो, It's your right. यानी कि ऐसे परिवार भी फैशन के क्षेत्र में अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं। यहां दिल्ली की लड़की है, यदि उसका नंबर मैरिट लिस्ट में चेन्नई में आता है, तो उसे चेन्नई जाना पड़ता है, किसी का गांधीनगर में, किसी का कोलकाता में नंबर आता है, तो उसे जाना पड़ता है। यह बहुत difficult है। यह ठीक है कि एक साल के बाद अगर medical gounds पर कोई प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें उनके क्षेत्र में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोर्सेज तय होते हैं, इस हिसाब से इनको वहां जाना ही पड़ता है। पेरेंट्स, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, कितने ही पेरेंट्स आकर रोते हैं कि हमारी बच्ची को मुंबई सूट नहीं करता है, मुंबई वाले आकर रोते हैं कि कोलकाता सूट नहीं करता है। इसका रास्ता हम निकाल रहे हैं कि long run पर जहां भी पेरेंट्स चाहें या स्टूडेंट्स चाहें, वहीं इनको रहने की सुविधा हो। इतना ही नहीं, हमने गर्ल्स होस्टल के लिए कंपलसरी स्टैंडर्ड बनाया है कि लड़के तो कहीं भी ऐडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए जरूर गर्ल्स होस्टल होने ही चाहिए। इसके लिए गांधीनगर में होस्टल का निर्माण आरंभ हुआ है, अभी मैं मुंबई गया था, वहां भी होस्टल बनना आरंभ हुआ है। हम प्रॉयोरिटी देते हैं कि डेढ़ साल की जगह एक साल में होस्टल पूरा करिए, कई जगहों पर हम किराए पर भी होस्टल लेते हैं। इस तरह हमारी गर्ल्स होस्टल की प्रॉयोरिटी है।

श्री शेख खबीर उद्दीन अहमद और श्री मोइनुल हसन साहब ने खादी और हैंडलूम के बारे में बताया। इसके लिए हमने दूरदराज के इलाकों में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के या दूसरे artisans हैं, उनके लिए कुछ clusters तय किए हैं और हमारे स्टूडेंट्स वहीं जाते हैं। पांच-छह प्रदेश इसमें इन्वॉल्व हैं और वहां के 10,000 लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, इन शिल्पियों के साथ मिलकर हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। इसमें जो राज्य शामिल हैं, वे हैं - कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। आपकी कांस्टीटयुऐंसी में या आपके राज्य में यदि आपको ऐसा लगता है कि यह इलाका, यह जिला तजर्पेदे के लिए बहुत अच्छा एरिया है, तो यदि वहां छप्प्ज का सेंटर है, तो वहां छप्प्ज के स्टूडेंट्स जाने चाहिए, इसके अलावा यदि छप्प्ज के नए सेंटर खोलने का मौका आता है, तो इन स्टूडेंट्स को प्रॉयोरिटी दी जाए कि वे वहां जाएं और इन लोगों को फैशन सिखएं। मैं समझता हूं कि जो लोग दूरदराज के इलाकों में हैं, उनको इससे बहुत फायदा होगा।

उपसभापति महोदय, श्री गांधी आज़ाद जी ने कम कपड़ों की बात कही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि छप्प्ज के एक फंक्शन में मैं और कॉमर्स मिनिस्टर गए थे। वहां मैंने डिजाइनर लोगों से कहा कि चूंकि मैं जमगजपसम क्षेत्र से हूं, इसलिए आप लोग ऐसे फैशन के वस्त्र बनाइए,

ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनें और कपड़े की खपत ज्यादा हो। कम कपड़ों की दुनिया से हटकर, ऐसे डिजाइन के वस्त्र बनाए जाएं, ताकि लोग ज्यादा कपड़े पहनें। Western Countries से या कहीं से भी फैशन का जो भी नमूना आता है, वह हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है। लोग अगर चाहते हैं कि ऐसा फैशन चाहिए, तो वैसा फैशन आता है। फैशन को introduce करने वाला अपनी imagination से यह कल्पना करता है। मैं समझता हूं कि फैशन कोई नयी चीज नहीं है। हिंदुस्तान बहुत फैशनेबल है। यह नज़र की तकलीफ है। मुख्य बात यह है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप गांवों में जाएंगे, तो हमारी बहनें अभी भी नाभि के नीचे कपड़े पहनती हैं। यह routine सी बात है। ऐसी हजारों बहनें आपको कच्छ और अहमदाबाद में मिलेंगी। आपके क्षेत्र में भी होंगी, tribal लोग भी होंगे, जिनके लिए यह फैशन नहीं है, it is routine. अब backless वाला मामला है, आप गांवों में जाइए, वहां वे अभी भी ऐसे ही कपड़े पहनती हैं।

श्री गांधी आज़ाद: वे मजबूरी में पहनती हैं, वहां गरीबी है।

श्री शंकर सिंह वाघेला: नहीं, गरीबी नहीं है, वह routine है।

श्रीमती वृंदा कारत: नहीं, गरीबी की वजह से नहीं है।

श्री शंकर सिंह वाघेला: मैं tribal लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग शहरों की periphery में रहते हैं, वे भी ऐसे कपड़े पहनते हैं। यह एक routine सा है, अपने समाज की व्यवस्था के अनुसार वे ऐसे कपड़े पहनते हैं। backless वाला मामला है, वह भी पहनते हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): मंत्री जी, नंगे दो ही तरह के होते हैं – कुछ लोग वक्त के मारे होते हैं, कुछ शौक से नंगे होते हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला: यह सही है कि फैशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैशन के नाम पर आप शरीर प्रदर्शन करें, जिससे देखने वाले को विकृति लगे। किसी महिला का बच्चा जब स्तनपान करता है, तो हमारे मन में कभी भी विकृति नहीं आती है, लेकिन ऐसे ही अगर उसको रखा जाएगा, तो जरूर दिमाग में विकृति आती है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे यहां फैशन की दुनिया देखिए, आप खजुराहो जाइए, आप कोणार्क जाइए, आप अजंता-एलोरा जाइए, कहीं कोई कमी नहीं है। मैं on record कहना चाहता हूं कि पेरिस और Western Countries को भी India के पास आना पड़ेगा, क्योंकि India के पास जो fashion imagination है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह fashion hub बने, ऐसी हमारी कैपेसिटी है। मैं समझता हूं कि इस कैपेसिटी के हिसाब से निफ्ट का बिल जरूर हमारी मदद करेगा। जितने भी माननीय मैम्बर्स ने इसमें योगदान किया है – महेन्द्र जी, मैडम दुर्गा जी, गांधी आज़ाद जी, अहमद साहब, बागड़ोदिया साहब, मारू जी ने, मैं सबका आभारी हूं। इस बिल से इसका स्टैंडर्ड हाई बनेगा,

बच्चों में विश्वास आएगा, पैरेंट्स को उन्हें भेजने के लिए विश्वास आएगा कि हमारे बच्चे को डिग्री मिलेगी, डिग्री के साथ वे दुनिया भर में इसका व्यापार बढ़ा सकते हैं, इनको वीजा भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास करें। अभी इसे लोक सभा में भी ले जाना पड़ेगा। आपने अच्छे सुझाव दिए हैं। इस हिसाब से मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे सर्वसम्मति से पास करें, ताकि नई पीढ़ी, जो फैशन की दुनिया में आगे आ रही है, इसे मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to establish and incorporate the National Institute of Fashion Technology for the promotion and development of education and research in fashion technology and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one amendment (No. 3) by the hon. Minister.

Clause 2 - Definitions

SHRI SHANKERSINH VAGHELA: Sir, I move:

3. That at page 2, for lines 10—14, the following be substituted, namely,—

'(e) "fashion" includes a popular trend or a lifestyle, specially in styles of dress and ornament or manners or behaviour or the business of creating, promoting or studying styles in vogue or the designing, production and marketing of new styles of goods, such as clothing, accessories, craft, cosmetics; and the words "fashion technology" with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly;'

The question was put and the motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there are eight amendments (No. 4—11) by the hon. Minister.

Clause 3 - Establishment of the Institute

SHRI SHANKERSINH VAGHELA: Sir, I move:

4. That at page 2, *after* line 37, the following be *inserted,* namely,—

"(b) three Members of Parliament, two from Lok Sabha to be nominated by the speaker of Lok Sabha and one from Rajya Sabha to be nominated by the Chairman of Rajya Sabha;"

5. That at page 2, line 38, *for* the bracket and letter "(b)" the bracket and letter "(c)" be *substituted.*

6. That at page 2, line 39, *for* the bracket and letter "(c)" the bracket and letter "(d)" be *substituted.*

7. That at page 2, line 41, *for* the bracket and letter "(d)" the bracket and letter "(e)" be *substituted.*

8. That at page 2, line 43, *for* the bracket and letter "(e)" the bracket and letter "(f)" be *substituted.*

9. That at page 2, line 46, *for* the bracket and letter "(f)" the bracket and letter "(g)" be *substituted.*

10. That at page 3, line 1, *for* the bracket and letter "(g)" the bracket and letter "(h)" be *substituted.*

11. That at page 3, *after* line 11,the following be *inserted,* namely,—

"(7) It is hereby declared that the office of the member of the Board of Governors shall not disqualify its holder for being chosen as, or for being, a member of either House of Parliament."

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 to 34 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, there is one amendment (No. 2) by the hon. Minister.

Clause 1 - Short title and commencement

SHRI SHANKERSINH VAGHELA: Sir, I move:

2. That at page 1, line 4, for the figure "2005" the figure "2006" be substituted.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Enacting Formula, there is one amendment by the hon. Minister.

Enacting Formula

SHRI SHANKERSINH VAGHELA: Sir, I move:

1. That at page 1, line 1, for the words "Fifty-sixth" the words "Fifty-seventh" be substituted.

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI SHANKERSINH VEGHELA: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the reply of the hon. Minister on the discussion on the working of the Ministry of Information and Broadcasting.

Discussion on working of the Ministry of Information and Broadcasting — Contd.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI): Mr. Deputy Cairman, Sir, in the last Session of Parliament, I had the privilege to initiate the discussion on the working of my Ministry, i.e., the Ministry of Information and Broadcasting. I am highly thankful to all the distinguished Members, like Shri Rajeev Shukla, Shri Ravi Shankar Prasadji, Shrimati Brinda Karatji, Shri Shyam Benegalji, Shri Perumalji, Shrimati Jaya Bachchanji, Shri E.M. Sudarsana Natchiappanji, Shri Shatrughan Sinhaji, Shri R. Shunmugasundaramji, Shri Tarlochan Singhji, Shri Moolchand Meenaji, Shri Manoj Bhattacharyaji, Shri Ram Narayan Sahuji, Shri Kripal Parmar, Shri Shantaram Laxman Naikji, Shri V. Narayanasamy and Shri Janardhana Poojaryji for their rich contribution to the debate. A few of them are no more the Members of the House, yet, I value their suggestions and their understanding of the present scenario that is being there in the film world, in the Prasar Bharati and in the print media.